



प्रकाशक/स्वामीत
रजनी (पुत्री-महेश धावनिया)

डाक पंजियन संख्या : JaipurCity/423/2017-19

श्री बाबा

प्रधान कार्यालय-सी-57, महेश नगर, जयपुर-15, मो.-9928260244

हिन्दी मासिक समाचार पत्र



7073909291 E-mail:shreebab_2008@yahoo.com



वर्ष : 11 अंक : 8 आर.एन.आई. नं. : RAJHIN/2008/24962



जयपुर, 5 अक्टूबर, 2018

मूल्य : 5 रुपए प्रति

पृष्ठ : 4

राजनीति की कबड्डी में पटखनी देना मुझे आता है: पायलट

सांगोद (कोटा)। कोटा जिले के सांगोद में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर मंगलवार को आयोजित सभा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिव पायलट ने कहा कि हमारी संस्कृति में बड़ों का आदर किया जाता है। ये हमारे संस्कार हैं, लेकिन राजनीति की कबड्डी में पटखनी देना मुझे अच्छी तरह आता है। पायलट ने राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि आज हाड़ीती में किसान



आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन प्रदेश की मुख्यमानी के पास इन

किसानों के परिवारों के पास जाकर दुख-दर्द बांटने तक का समय नहीं है। उन्होंने भाजपा की प्रदेश की राजनीति में चल रहे घमासान पर भी जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि वसुंधरा हाड़ीती आती है तो भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नागौर जाते हैं, भाजपा की अंदरूनी लड़ाई खुलकर लोगों के सामने आ चुकी है। (शेष पृष्ठ 2 पर)

जिला स्तरीय बैरवा सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह सम्पन्न

कोरौली। नादोती में दिनांक 30 सितंबर 2018 को जिलास्तरीय बैरवा महा सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन श्री चिनोद कुमार बैरवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हरिनारायण बैरवा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे।



उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आरक्षण और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से कोई

अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जन जाति की छात्राओं की भाँति अनुसूचित जाति की मेघावी छात्राओं (शेष पृष्ठ 3 पर)

एनएफआईसीआई की कांफ्रेंस एवं कार्यशाला

जयपुर। देश भर के सूचना आयोगों ने सूचना का अधिनियम की मूल भावना के तहत पारदर्शिता व लोकहित को प्राथमिकता देते हुए ज्यादा से ज्यादा सूचनाओं को सूचना का अधिकार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत स्वतः सार्वजनिक करने की आवश्यकता प्रकट की है। जयपुर में सूचना आयोगों के संगठन नेशनल फैडरेशन आफ इंफार्मेशन कमीशनसं इन इण्डिया एन एफ आई सी आई की दो दिवसीय कार्यशाला में यह संकल्प लिया गया। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संयोजन में आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता केन्द्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त श्री आर.के.माथुर ने की। इसमें देश भर के 16 राज्यों से 15 मुख्य सूचना आयुक्तों एवं 5 सूचना आयुक्तों ने भाग लिया।

अखिल भारतीय बैरवा विकास संघ जिला शाखा अलवर के तत्वाधान में ग्राम माता डी राजगढ़ में बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि माननीय जितेंद्र जी गोठवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज जी गोठवाल प्रदेशाध्यक्ष भगवान वर्मा, प्रभु काकरवाल, रामकरण कुण्डारा, गिरिराज रेसवाल जय नारायण जी एवं अन्य अतिथि गण मूर्ति का अनावरण करते हुए प्रतिभाओं को सम्मानित किया



डॉ. अंबेडकर का एससी एसटी ओबीसी वर्ग के उत्थान का सपना अधूरा: राम लुभाया

जयपुर। डॉ भीमराव अंबेडकर एससी एसटी ओबीसी वर्ग के उत्थान का सपना अब तक अधूरा है इनके उत्थान हेतु संवैधानिक अधिकारों की व्यवस्था की

आजादी के 71 वर्ष बाद भी इन जातियों को सामाजिक अर्थात् व शैक्षणिक अधिकार व शैक्षणिक अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ है यह विचार सेवनिवृत्त आईएस एवं पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव व पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त राजस्थान सरकार ने राजस्थान विश्वविद्यालय स्थित अरावली छात्रावास में आयोजित अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के संवैधानिक एवं व्यवहारिक पक्ष विवेष पर विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए दिए। उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन हेतु सामर्थ्य प्राप्त करनी

पंकज कुमार धावनिया सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष निर्वाचित सचिवालय के इतिहास में पहली बार एस.सी. का अध्यक्ष बना

जयपुर। राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के चुनाव हाल ही में संपत्र हुए जिसमें पंकज कुमार धावनिया अध्यक्ष निर्वाचित हुए। निर्वाचन अधिकारी प्रेम नारायण सेन ने बताया कि चुनाव में कुल 794 मत डाले गए जिनमें 287

मत पंकज कुमार धावनिया, देवेंद्र सिंह शे खावत को 270, अभिमन्यु शर्मा को 169, कपिल देव को 65, एवं तीन मत रहे हुए हैं। प्रकार से पंकज कुमार धावनिया 17 मतों से विजय हुए। मतदान के बाद पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई।

गौरतलब है कि सचिवालय के चुनाव में पंकज कुमार धावनिया अनुसूचित जाति वर्ग के पहले कर्मचारी अध्यक्ष बने हैं। इस अवसर पर सचिवालय के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों एवं परिवारजन द्वारा माला पहनाकर सम्मान कर बधाई दी गई।



प्रांतीय बैरवा प्रगति संस्था के प्रदेशाध्यक्ष महेश धावनिया द्वारा पंकज कुमार धावनिया का सचिवालय संघ का अध्यक्ष बनने पर माला पहनाकर बधाई देते हुए।

बैरवा छात्रावास का प्रथम तल लोकार्पण समारोह 14 अक्टूबर को

जयपुर। बैरवा शिक्षा प्रचार एवं सहायतार्थ समिति के तत्वाधान में जयपुर स्थित सेन्ट्रल स्पाइन-श्रीकिशनपुरा, जगतपुरा, जयपुर में बैरवा छात्रावास भवन के प्रथम तल का लोकार्पण समारोह रविवार, 14 अक्टूबर, 2018 को प्रातः 11.30 बजे छात्रावास प्रांगण में आयोजित किया जायेगा। समारोह के मुख्य अतिथि श्री प्रशान्त बैरवा, सचिव, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी होंगे तथा समारोह की अध्यक्षता डॉ. आर.सी. बंशीवाल, वरिष्ठ प्रोफेसर (आर्थी), सवाईमानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर करेंगे।

समारोह में प्रथम तल के निर्माण में जिन भागीदारों ने कमरे निर्माण के पेटे राशि रूपये 1,51,000 अथवा इससे अधिक राशि दी है उनका तथा निर्माणार्थी में इस कार्य में जिन महानुभावों का विशेष सहयोग रहा है उनका सम्मान किया जायेगा।

समाचार विज्ञापन संकलन

श्री बाबा समाचार पत्र की प्रकाशन तिथि प्रत्येक माह की 5 तारीख है। अतः समाचार एवं विज्ञापन आदि के प्रकाशन के लिए विज्ञप्ति, फोटो आदि सामग्री माह की 20 तारीख तक पूर्ण विवरण के साथ भिजवा दें। सम्पर्क करें:

श्री बाबा whatsapp

7073909291

सी-57, महेश नगर, 80 फीट रोड, जयपुर-15

मो.-9928260244 E-mail : shreebab_2008@yahoo.com

सम्पादकीय किसानों का आंदोलन

यह टकराव लगभग तय ही था। 23 सितंबर को जब हरिद्वार से किसान क्रांति यात्रा शुरू हुई थी, तो इसकी आशंका तभी से थी। आयोजक भी यह अच्छी तरह जानते होंगे कि 2 अक्टूबर को जब दिल्ली में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के आयोजन चल रहे होंगे और दुनिया भर के अतिथि यहां मौजूद होंगे, तब उन्हें ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर लदकर किसान घाट नहीं पहुंचने दिया जाएगा, जो महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट का ही एक हिस्सा है। राजनीतिक विरोध-प्रदर्शन के कार्यक्रम ऐसे अवसरों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। और यही हुआ थी। हजारों की संख्या में उमड़े किसानों को दिल्ली की सीमा पर बैरीकेड और दफा-144 वर्गैरह लगाकर रोक दिया गया। उस पर भी जब वे अड़े रहे, तो उन्हें पानी की धार और लाठियों से रोकने के बे तरीके भी अपना लिए गए, जो ऐसे मौकों की एक अनिवार्य रूप बनते जा रहे हैं। लेकिन इतने भर से ही आंदोलन करने वालों को वह देशवापी प्रचार हासिल हो गया, जो शायद तब न हो पाता, जब वे नारे लगाते हुए किसान घाट पहुंचते और अपने विरोध आयोजन को निपटकर लौट जाते। दिल्ली की सीमाओं पर जो हुआ, वह अगले कुछ दिन के लिए उनकी राजनीतिक पूँजी बन गया है। लेकिन जरूरत यह भी है कि देश की किसानी जिस संकट से गुजर रही है, उसे आंदोलन की इस नाटकीयता और पुलिस की कार्रवाई से अलग देखा जाए। यह पहला मौका नहीं, जब किसान खेतों को छोड़कर सड़कों पर उतर आए हों। अभी कुछ सप्ताह पहले ही महाराष्ट्र के किसानों ने नासिक से मुंबई तक लॉना मार्च की थी। वे महाराष्ट्र विधानसभा का घेराव करना चाहते थे। जुलाई महीने में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने दिल्ली में किसानों का एक बड़ा प्रदर्शन किया था। सिंतंबर की शुरुआत में 23 राज्यों के किसानों ने दिल्ली से रामलीला मैदान तक एक बड़ा प्रदर्शन किया था। भले ही किसानों के ये प्रदर्शन अलग-अलग समय और देश के अलग-अलग हिस्सों में हुए हों, लेकिन इनकी बहुत सी मार्गों समान रही हैं। मसलन, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पूरी तरह लागू करना, फसलों के ज्यादा समर्थन मूल्य देना, कर्ज माफी, किसानों के लिए पेंसन की व्यवस्था बनाना वर्गैरह। ताजा आंदोलन में जो किसान उमड़े, वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रन्थ क्षेत्र के थे और उनकी एक बड़ी समस्या है, चीनी मिलों से बरसों के बकाये का न मिलना।

सदस्यता शुल्क

वार्षिक सदस्यता

100 रुपए

विशिष्ट द्विवार्षिक सदस्यता

500 रुपए

साथ में पाएं दो वैवाहिक एवं एक क्लासीफाइड डिस्प्ले

विज्ञापन

बिल्कुल मुफ्त

आजीवन सदस्यता

2100 रुपए

संरक्षक सदस्यता

5100 रुपए

बहुजनों की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन ?

गतांक से आगे

हमें डर सिर्फ यही है कि आज भ्रष्टाचार के मूल कारण 'जातिगत वर्ग संघर्ष' को छिपाकर उससे फैली अव्यवस्था के मीडिया में प्रचार की गति हमारे संघर्ष की गति से तेज न निकले। धन और मीडिया के बल पर सोच-समझे षड्यंत्र के तहत जो अराजकता फैलाई जा रही है, उसे संविधान की विफलता साबित किया जा सकता है। और तब हमारी भोली-भली जनता संविधान का विरोध करके अपने पैर पर कुलहड़ी मार लेगी। इसीलिए बाबा साहब पहले ही कह गए थे 'संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, उसे मानने वाले बुरे होंगे तो उसका लाभ नहीं हो पायेगा।' जनता का नाम लेकर सत्ता पलट या संविधान पलट न हो जाये, ऐसे होने पर हमारे विरोध और अपने पक्ष का संविधान या कानून

बना लेंगे। इसलिए सावधान!

मैं समझ सकता हूं कि हमारा सक्षम वर्ग किसी नेता की रैली में भीड़ बढ़ने का काम तो नहीं करेगा, पर वो उससे भी कहाँ ज्यादा जरूरी काम कर सकता है। कुछ खास नहीं तो जो कर सकते हो वो तो करो जैसे - अंबेडकरवादियों को बोट करो, उन्हें चंदा दो, मिशन की किताबें खरीद कर अपने लोगों में बांटों, विचार और सुझाव देना, लेखन कार्य करना, एन.जी.ओ. ट्रस्ट, स्कूल में किसी मेधावी बहुजन को स्कॉलरशिप देना आदि। जो

जिस लायक है उसे वही काम करना चाहिए, जो भीड़ बढ़ा सकता है वो भीड़, जो धन दे सकता वो धन, जो विचार दे सकता है वो विचार, कुछ तो करो, संघर्ष के लिए सब कुछ जरूरी है। भगवान् बुद्धा ने कहा है कि संसार में तीन प्रकार के लोग हैं : 'एक जो केवल अपना भला करते हैं दूसरों का नहीं, दूसरे जो अपना भला नहीं करते केवल दूसरों का भला करते हैं, तीसरे जो अपना भी भला करते हैं व दूसरों का भी। ये ही श्रेष्ठ हैं।'

इनमें से हमें तीसरा बनना है। बिना जमीन वालों को अंबेडकर मिशन ने जमीन के पट्टे दिलाये, बिना नौकरियों वालों को नौकरी करने लायक बनाया और नौकरियां दिलाई। अब ये लोग उस मिशन के लिए कुछ न करें तो क्या समस्त कौम पतन की तरफ नहीं चली जाएगी? बहुजनों का सम्पन्न होना विरोधियों को खटक रहा है और अंदर ही अंदर वो दमन की नीति बनाकर चल रहे हैं।

अगर ये सफल हो गए तो क्या होगा, कभी सोचा। पता नहीं हमारे सक्षम लोग ये क्यों नहीं समझते कि जब भी बहुजनों का दमन किया जाएगा, इनको भी बक्शा नहीं जाएगा।

18 मार्च 1956 को को बाबा साहब अंबेडकर ने दुःखी होकर आगरा के बे-जमीन वाले लोगों ; बहुजन समाज को इकट्ठा करके ऐलान किया था कि 'अंग्रेजों ने मेरी बात मान ली थी, लेकिन दुनिया की हालत बदलने के कारण उनको देश छोड़ना पड़ा। अंग्रेज चले गये। जिन लोगों के हाथों में जमीन आई। वो कहते हैं अगर बे-जमीन वाले लोगों को हमने खेत दे दिये तो हमारे खेतों में मजदूरी कौन करेगा? इसलिए मैं मजबूर हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने उस वक्त आगरा में दुःखी होकर लाखों बे-जमीन वाले लोगों से कहा कि ये काम, जिसकी अंग्रेजों ने हां भरी थी कि वो हमारे लिए सेपरेट इलेक्ट्रोरेट बनायें, सेपरेट सेटलमेंट बनायें, अलग से हमारे रहने के लिए बसिस्तां बनायें, जिनमें हम करोड़ों लोग रहेंगे और अपने बलबूते पर अपने एमएलए चुनकर भेजेंगे और लोकल सेल्स गर्मेंट खुद चलायेंगे। इस बात को अंग्रेजों ने मान लिया था, लेकिन आज की सरकार नहीं मान रही है। मेरा ज्यादा समय पढ़ाई-लिखाई के मामले में, रिजर्वेशन के मामले में, हमारे समाज में इंजीनियर्स, डॉक्टर, वकील पैदा हो, अधिकारी पैदा हो, कर्मचारी पैदा हो, इसमें मेरा बहुत ज्यादा समय लग गया है। लेकिन मैं आज देख रहा हूं कि ये पढ़े-लिखे कर्मचारी। ये तो

जाहीरी स्तरीय सभा सांगोद स्थित महाराव भीम सिंह स्टेडियम में पूर्व मंत्री भरतसिंह के आहान पर आयोजित थी।

प्रधानमंत्री ने लोगों की जेब में डाका डाला: तरुण कुमार

एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव व राजस्थान प्रभारी तरुण कुमार ने कहा कि देश में आने वाले चुनाव विचारधाराओं के आधार पर लड़े जाएंगे। कांग्रेस की विचारधारा देश को एकता व सौहार्द बढ़ाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने लोगों की जेब में डाका डालकर गरीबों का पैसा उद्योगपतियों को

एक क्लास; वर्ग बनकर रह गये, एक अलग कास्ट बनकर रह गये हैं। जिन लोगों में ये पैदा हुए हैं, उन लोगों का इनको कोई खाल नहीं है। हमारा गरीब समाज नीचे की ओर जा रहा है और ये अधिकारी लोग ऊपर को जा रहे हैं। इन दोनों का कोई मेल-मिलाप नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बढ़ती हुई उम्र में मैं लाठी लेकर आगे-आगे चलूंगा और आप लोग मेरे पीछे-पीछे चलें। अपने लोगों की बस्तियां बनाना, ये हमारी जरूरत है। आज की सरकार यह नहीं करना चाहती है। ये काम हमारा है, हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत हमें ही पूरी करनी होगी।' मान्यवर कांशीराम जी ने 7 जुलाई 2002 को दिल्ली के रामलीला मैदान में नारा लगाना शूरू किया था - 'जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है।' हम लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के प्रयासों से प्रेरित होकर, जो हमें बोट का अधिकार लेकर दिया, उस बोट के अधिकार को ध्यान में रखकर हम लोगों ने नारा बनाया है, 'बोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।' आज हमारे लोग चौधरी बन कर उन्हें विभिन्न धर्म स्थलों, सत्संग आदि में अपना समय और दान दे रहे हैं, जहां हमारे दमन नीति के सृजक बैठे हैं।

हमारे लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि इनका नाम और रूप बदल जाता है, पर नियत कभी नहीं बदलते। पता नहीं हमारे सक्षम लोग ये कब समझेंगे कि आज जिस खुशहाली से वो जीवन बिता रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ है। जिसको आगे ले जाना इनका कर्तव्य है। बाबा साहब ने हमें जो उपलब्धियां दिलाई। उनका आनंद तो लेते हैं, पर उनके संघर्ष से भी तो कुछ प्रेरणा भी तो लो, बाबा साहब की निम्न पक्षियां देखिये - 'जब मेरे प्यारे बेटे गंगाधर का बीमारी के कारण निधन हुआ, तब उसके मृतदेह को ढकने के लिए नए कपड़े लाने के लिए लोगों ने मेरे से पैसे मांगे, पर मेरे पास उतने भी पैसे नहीं थे तब मेरी पत्नी ने साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर दिया और हम गंगाधर को शमशान ले गए। मैंने मेरी जिंदगी में गरीबी के जो दिन देखे हैं, वो भारत के किसी नेता ने नहीं देखे होंगे, किर भी मैंने मेरी गरीबी के कारण कभी म

इंजीनियरिंग कॉलेजों के सरकारी होने से सबको लाभ ही है

यदि वर्तमान सरकार आचार संहिता लागू होने से पहले राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों को पूर्णतः सरकारी बना देती है तो यह न केवल सरकार की एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी, बल्कि राज्य को विज्ञान, तकनीकी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नई ऊँचाईया देने के मामले में भी अभूतपूर्व निर्णय होगा।

किसी भी देश अथवा भू भाग के विकास में विज्ञान का बहुत योगदान होता है। विज्ञान के ही कई आयाम हैं जिनमें तकनीकी, इंजीनियरिंग मेडिकल आदि से लगभग सभी परिचित हैं। आज यदि अमेरिका, इंग्लैण्ड, रूस, जापान, प्रांस आदि देश हमसे आगे हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अधिकतर अविष्कार इन देशों में हुए हैं और दूसरे देशों ने उनके पेटेण्ट खरीदे हैं या उनका उपयोग-भर किया है। इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिये कॉलेजों का होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि कम कीमत पर यह विज्ञान के एकाधिकार का खात्मा:- अभी स्वायत्तंत्रासी होने से ये अपने नीतिगत फैसले स्वयं ले सकते हैं। कई बार इनके निर्णय छात्रों और कर्मचारियों के विरोध में होते हैं तो कई बार ऐसे निर्णय लेते ही नहीं हैं जो कि कर्मचारियों के हित के हैं। उदाहरणार्थ- चाहे जिस व्यक्ति को कॉलेजों में क्लास्टर अलॉट कर देना और जिसको आवधकता हो, उसे नहीं देना, यहाँ तक कि जिसका स्वयं का मकान कॉलेज की बगल में हो उससे वर्षों तक क्वार्टर खाली नहीं करवाना, छात्रों के लिये कैंटीन आदि की सुविधा न होने देना, पुस्तकालयों की व्यवस्था सही नहीं होने देना, ताकि सम्बन्धियों की दुकानें ठीक से चल सके। कॉलेज में सार्वजनिक सुविधाओं की साफ-सफाई में जानबूझकर लापरवाही करने देना और जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा सुनवाई नहीं करना, क्योंकि प्राचार्य का वरदहस्त होना। और भी कई कार्य ऐसे होते हैं जिनसे पदस्थ उच्च कर्मचारियों के एकाधिकार की झलक मिलती है। इससे गरीब तबके के तथा आर्थिक रूप से कमजोर कर्मचारी मन मारकर नौकरी करने को विवश होते हैं जबकि उच्च पदस्थ और आर्थिक रूप से सम्पन्न कर्मचारियों पर कोई असर नहीं पड़ता है। हमारे कॉलेज में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का मामला इसी कारण से आज तक अटका पड़ा है। वैसे इस स्कीम से हर फेकल्टी मेम्बर की ग्रेड पे बढ़ती थी। किसी की 6000 से 7000 तो किसी की 7000 से 8000, कुछ की 8000 से 9000 व 9000 से 10000 भी होनी थी और इस प्रकार लगभग सभी को फयदा होना था, परन्तु पचासों बार मीटिंग की, कभी 2-3 तो कभी 5-7 मेम्बर्स से अधिक नहीं आये। गम्भीरता से किसी ने इस मामले को लिया ही नहीं और पिर प्राचार्य तथा लेखाधिकारी इसी फूट का फयदा उठा कर मनमाने ढंग से नचाते रहे। आज राज्य के कई इंजीनियरिंग कॉलेजों को न केवल 6000 से 7000 ग्रेड पे का फयदा मिल चुका है, बल्कि 7000 से 8000 का फयदा भी मिल चुका है और आगे की ग्रेड पे के लिये उनकी फईलों पर कार्रवाही चल रही है और आचार संहिता लगने से पहले-पहले सारे लाभ उन्हें मिल सकते हैं। हमारे कॉलेज में 6000 से 7000 के लिये तरस रहे हैं!!

आज के युग को देखते हुए यह आवधक है कि राज्य के सभी स्वायत्तंत्रासी इंजीनियरिंग कॉलेजों को पूर्णतः सरकारी कॉलेजों का दर्जा दे दिया जाये और इनका सारा हिसाब-किताब भी राज्य सरकार के ही अधीन हो। इससे आम जनता से लेकर कार्मिकों और सरकार तक, सबको फयदा ही फयदा होगा।

1. जनता को लाभ:- वर्तमान में स्ववित्तपोषित सीट पर लगभग 70-75 हजार रुपये प्रतिवर्ष फैसली जीती है। अगर कॉलेज सरकारी हो जाते हैं तो दूर्योग फैसली माफहो जायेगी, अतः ली जाने वाली फैसली लगभग आधी हो जायेगी। इससे निर्धन छात्रों की आर्थिक परेशानी कम होगी।

इसके अलावा आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति भी मिलने लगेगी। मैं पिछले तीन वर्षों से टेक्सटाइल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा में छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्य देख रहा हूँ। सरकार के नियमानुसार आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति तभी मिलती है जब वे राजकीय कॉलेजों में ही पढ़ रहे हैं। जब भी हमारे कॉलेज का कोई छात्र इस कैटेगरी में फर्म भरता है, उसका फर्म उपरोक्त कारण से रद्द हो जाता है। पिछले कई सालों से इस कॉलेज से इस वर्ग के किसी भी छात्र को इसी कारण कोई छात्रवृत्ति नहीं मिली है। अपने स्तर पर हम सभी कोशिषें कर चुके हैं, पर कॉलेज को सरकारी बनाना तो राज्य सरकार का ही कार्य है। इससे निर्धन वर्ग के छात्रों को दोहरा लाभ होगा, एक तो

फैसली कम लगेगी, दूसरे उन्हें छात्रवृत्ति भी मिल सकेगी।

2. कॉलेज के प्राचार्य और वारिशों के एकाधिकार का खात्मा:- अभी स्वायत्तंत्रासी होने से ये अपने नीतिगत फैसले स्वयं ले सकते हैं। कई बार इनके निर्णय छात्रों और कर्मचारियों के विरोध में होते हैं तो कई बार ऐसे निर्णय लेते ही नहीं हैं जो कि कर्मचारियों के हित के हैं। उदाहरणार्थ- चाहे जिस व्यक्ति को कॉलेजों में क्लास्टर अलॉट कर देना और जिसको आवधकता हो, उसे नहीं देना, यहाँ तक कि जिसका स्वयं का मकान कॉलेज की बगल में हो उससे वर्षों तक क्वार्टर खाली नहीं करवाना, छात्रों के लिये ही होती हैं जिनका फयदा आज तक स्वायत्तंत्रासी संस्थानों के कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है, वह भी सरकारी होने पर मिलने लग जायेगा।

3. समय का सुपुण्योग अध्यापन, रिसर्च और कॉलेज के विकास कार्यों में कर सकें:- जैसा कि पूर्व के बिन्दू में लिख चुका हूँ- हमारे कई फेकल्टी मेम्बर्स को पाँचवें वेतनमान का तो कईयों को छठे वेतनमान के अनुरूप मिलने वाले लाभ का इंतजार है। इसी को लेकर हम लगभग 6-7 साल से संघर्षरत हैं। हमारे घट्टे और हजारों रुपये इस बेकार के बेहदा काम में पुंक चुके हैं। लेकिन यह लेख लिखे जाने तक हमें न पाँचवें वेतनमान के अनुरूप लाभ मिला, न छठे के अनुरूप। सातवें के अनुरूप मिलना तो आसमान के तारे तोड़कर लाना जैसा है।

अगर यह कॉलेज सरकारी होता तो जो समय नेताओं-मंत्रियों के चक्र काटने में, अधिकारियों से मिलने में, धरने-प्रदर्शन करने और बड़े-बड़े लेख लिख कर छापने में व्यथ हुआ, वह छात्रों के उचित अध्यापन में, रिसर्च या कॉलेज के विकास हेतु कार्य करने में व्यतीत होता। अब भी यदि कॉलेज सरकारी हो जाता है तो आगे समय का सुपुण्योग हो पायेगा।

4. छात्रों को रोजगार मिलने में आसानी रहेगी:- वैसे डिग्री यूनिवर्सिटी देती है लेकिन सब कोई जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेजों और सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई और सुविधाओं के स्तर में कितना अंतर होता है। यह बात नियोजक भी जानते हैं और इसी के आधार पर छात्रों का प्लेसमेंट होता है।

5. वैज्ञानिक तरकी को बढ़ावा मिलेगा:- यह एक दुखद पहलू है कि इंजीनियरिंग, तकनीकी और विज्ञान क्षेत्र के फेकल्टी मेम्बर्स को अपने हक पाने के लिये धरने और प्रदर्शनों पर बैठना पड़ता है। जिनका समय प्रयोगशालाओं में छात्रों के साथ किसी तकनीकी समस्या पर वाद-विवाद करने और उसके लिए हमें अध्ययन करने में व्यतीत होना चाहिये, वह समयधरने और प्रदर्शनों जैसे फिल्म के कार्यों में जाया हो रहा है। जिन हाथों को सूचना के किसी कार्य में या चॉक-डस्टर लेकर क्लासों में विद्यार्जन कराना था, वे ही हाय-हाय, जिन्दाबाद-मुर्दाबाद में लहराने लग गये!! पूर्णतः सरकारी कॉलेज कॉलेज होने से जो भी निर्णय होगा, वह सभी कॉलेजों पर समान रूप से लागू होगा और उसका कोई विरोध भी होगा तो समाधान शीघ्र ही हो जायेगा।

अतः जितना जल्दी हो सके, सरकार को राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों को पूर्णतः सरकारी कर देना चाहिये।

-श्याम सुन्दर बैरवा
सहायक प्रोफेसर (वस्त्र रसायन)
(पीएच डी स्कॉलर)
माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल्स एवं
इंजीनियरिंग कॉलेज, भीलवाड़ा
सम्पर्क:- 01482-240433,
08764122431, पता-सी-323, आजाद
नगर, भीलवाड़ा. राजस्थान 311001

विटामिन कम करेंगे मोतियाबिंद का खतरा

रोजाना मल्टीविटामिन लेने से मोतियाबिंद का खतरा 10 फीसदी कम होता है।

इसके लिए हावर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने अमेरिका के कुछ डॉक्टरों को रोजाना मल्टीविटामिन



के साथ विटामिन सी, ई. और बीटा केरोटीन की खुराक दी व शेष को प्रायोगिक दवाएं।

शोधकर्ताओं ने पाया कि प्रायोगिक दवाएं लेने वाले डॉक्टरों में मल्टीविटामिन समूह की तुलना में मोतियाबिंद का खतरा ज्यादा था।

अदरक डायबिटीज में फायदेमंद

डायबिटीज काबू में तो रखा जा सकता है, लेकिन मेडिकल साइंस में अब तक ऐसी कोई दावा नहीं बनाई जा सकी



जाते हैं और धीरे-धीरे उनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। एक शोध के मुताबिक अदरक का अर्क न सिर्फ मोतियाबिंद होने से रोकता है बल्कि इससे पीड़ित रोगियों में ये रोग बढ़ने की गति को भी कम कर देता है। ताजी अदरक को पीसकर और इसमें थोड़ा कपूर मिलाकर सूजन व दर्द वाले अंगों पर लगाने से काफी आराम मिलता है। शरीर के किसी हिस्से पर चोट लगने पर अदरक का लोप लगाए। जब लेप सूख जाए तो इसे साफ करके गुजारने सरसों के तेल में मालिश करें। इसे एक-दो बार किया जाए तो मोच के दर्द में आराम मिलता है।

शुगर का स्तर कम होता है- ड

पत्रकारिता को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता: भण्डारी

जयपुर। गजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनीष भण्डारी ने कहा है कि



और अधिक बेहतर काम करेंगे। निवर्तमान अध्यक्ष राधारमण शर्मा ने अपने छह माह

पत्रकारिता ने लोकतंत्र के तीनों स्तम्भों को मजबूत करने का काम किया है, जिससे देश में लोकतंत्र की जड़े अधिक गहरी हुई हैं। भण्डारी सोमवार को पिंकसिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अभय जोशी के शपथ ग्रहण समारोह को

मुख्य अतिथि के रूप में सम्मोहित कर रहे थे। जस्टिस भण्डारी ने कहा कि पत्रकारिता के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है, ऐसे में पत्रकारिता को और अधिक मजबूत करने की आवश्यता है। इस दौरान उन्होंने प्रेस क्लब के अध्यक्ष अभय जोशी को शपथ दिलाई।

जोशी ने कहा कि वे प्रेस क्लब के विकास के लिए एक चौकीदार के रूप में

पायलट ने की सहकारी बैंकों के समझौते को लागू करने की मांग

जयपुर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने सहकारी बैंकों से संबंधित



कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पायलट ने भाजपा सरकार की कथित महंगाई बढ़ाकर जनता का शोषण करने की नीति को आर्थिक आपातकाल करार दिया है।

पायलट ने बताया कि भाजपा सरकार जिस नीति के तहत काम कर रही है, उससे आम जनता पर अप्रत्याशित महंगाई का भार पड़ रहा है और जनता की क्रय शक्ति बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल के दाम

राज्य सरकार कभी कमेटी गठित करने तो कभी वेतन समझौते का प्रावधान नहीं होने का बहाना बनाकर इस समझौते को लागू नहीं कर रही है।

आर्थिक आपातकाल की स्थिति =

आसामन छू रहे हैं।

नारायण मानव सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन



जयपुर। श्री नारायण मानव सेवा समिति द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रिको कॉलोनी पार्क, इण्डिया गेट, सीतापुर, जयपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक के तत्वावधान में पूर्ण किया गया, इस मौके पर मुख्य अतिथि राजस्थान पर्यावरण प्रकोष्ठ अध्यक्ष व समाज सेवी पुष्टेन्द्र भारद्वाज ने उपस्थित जन समूह को बताया कि रक्तदान मानव सेवा के लिये जरूरी कार्य है।

समिति अध्यक्ष चन्द्रमोहन बैरवा ने बताया कि शिविर में कुल 44 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया।

शिविर समाप्ति के पश्चात प्रत्येक रक्तदाता को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया व समाजसेवियों व भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर जनता दल युनाइटेड, सुशील कुमार सिन्हा, शशी शंकर झा, बिरदीचन्द शर्मा, सीताराम नेहरू, महेश चन्द्र सैनी, कृष्णकान्त टाटीवाल, महावीर सिंह गुर्जर, नेमीचन्द सैनी, राकेश महेश्वरी, संजीव झा, धर्मेन्द्र लोदिया, मदन नागरवाल, बालकिशन आकोदिया, सादिक हिस्ट्रुस्टानी, पवन, प्रभुनारायण व समस्त कार्यकारिणी सदस्य भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने बापू को श्रद्धासुमन अर्पित किए

जयपुर। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयन्ती के अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। श्रीमती राजे मंगलवार प्रातः गांधी सर्किल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर पहुंचीं और बापू को नमन कर उहें याद किया। श्रीमती राजे ने इस अवसर पर कहा कि हम सबको बापू के दिखाए हुए रस्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें सबको गले लगाकर अपने सपनों का राजस्थान बनाना है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्कूली छात्राओं द्वारा गए गए महात्मा गांधी के प्रिय भजन सुने। इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री कालीचरण सराफ, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जसबीर



सिंह, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती सुमन शर्मा, विधायक सुरेन्द्र पारीक तथा महापौर अशोक लाहोरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

आदिवासी मीना सेवा संघ एवं विभिन्न संगठनों के द्वारा आयोजित सम्मेलन सम्पन्न

दौसा। राजस्थान आदिवासी मीना सेवा संघ दौसा के तत्वाधान में आयोजित अनुसूचित जाति जनजाति के विभिन्न संगठनों की एकता के लिए 30 सितंबर 2018 को दौसा में आयोजित महा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए श्री हरिनारायण बैरवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बैरवा महासभा ने अपने उद्घोषन में कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में संवेधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सभी लोगों को आपसी भाईचारा बनाए रखते हुए संगठित होकर संघर्ष के लिए सजग रहने की आवश्यकता है श्री बैरवा ने अपने भाषण में निम्नलिखित प्रस्ताव रख कर सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया गया-

(1) आरक्षण मुदे पर कोई छेड़छाड़ बर्दाशत नहीं की जाएगी (2) 2, अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान दायर सभी मुकदमे वापस लिए जाएं (3) अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति का अविलंब भुगतान करवाया जाए (4) आरक्षण का अनुपात वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या

वृद्धि के अनुपात में अनुसूचित जाति को 16% के स्थान पर 17% एवं अनुसूचित जनजाति को 12% के स्थान पर 13% लागू किया जावे (5) अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं की भाँति अनुसूचित जाति की मेधावी छात्राओं के लिए भी निशुल्क स्कूली योजना प्रारंभ की जावे (6) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जावे (7) सामाजिक कुरीतियों जैसे मृत्यु भोज तीये की बैठक में भोजन नाश्ते की व्यवस्था पर प्रतिबंध, दहेज उन्मूलन के लिए

सामूहिक विवाह समारोह को बढ़ावा देना जैसे प्रस्ताव सभी सामाजिक संगठनों द्वारा पारित कर लागू करवाए जाएं जिससे फिजूलखर्ची रोकी जा सके (8) अत्याचार के मामलों में सभी समाज एक दूसरे को साथ दे।

कार्यक्रम में बाबूलाल बैरवा (महारा) प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय बैरवा महासभा रामेश्वर बंसीवाल प्रदेश उपाध्यक्ष हीरालाल प्रदेश प्रचार मंत्री बाबूलाल बैरवा टोरडा जिला अध्यक्ष दौसा धन्ना लाल बैरवा जिला महाप्रभाई सहित सैकड़ों बैरवा बंधुओं ने कार्यक्रम में भाग लिया।

150 प्रतिभाओं का हुआ सम्मान



जयपुर। डॉ. अम्बेडकर उत्थान परिषद, जयपुर इन्डिया गांधी पंचायती राज संस्थान, JLN मार्ग, जयपुर में 15 वा प्रतिभा सम्मान शमारोह खचाखच भेरे औडोटोरिम एवं आयोजित हुआ। जिसमें अनुसूचित जाति के प्रतिभावान छात्र छात्राओं तथा जिन्होंने IAS, RAS प्रतियोगी परीक्षा, 10, 12, स्नातक, स्नातकोत्तर परीक्षा या राज्य स्तर पर खेल क्षेत्र में, अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है, ऐसी 150 प्रतिभाओं का मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र द्वारा मुख्य अतिथि एम एस काला आईएस, व अनिल गोठवाल RPS, प्रशांत बैरवा सचिव प्रदेश कांग्रेस, महेंद्र कुमार बैरवा Addl.Chief Eng., आर एस जाटोलिया R.Ac.S, रामकिशोर रैगर R.Ac.S, प्रभुलाल बैरवा R.Ac.S दीपचंद नागर अभियंता आदि के कर कमलों से सम्मानित किया।